ई संदेश

12 फरवरी, 2026 | अंक -192

सात दिन, सात पृष्ठ

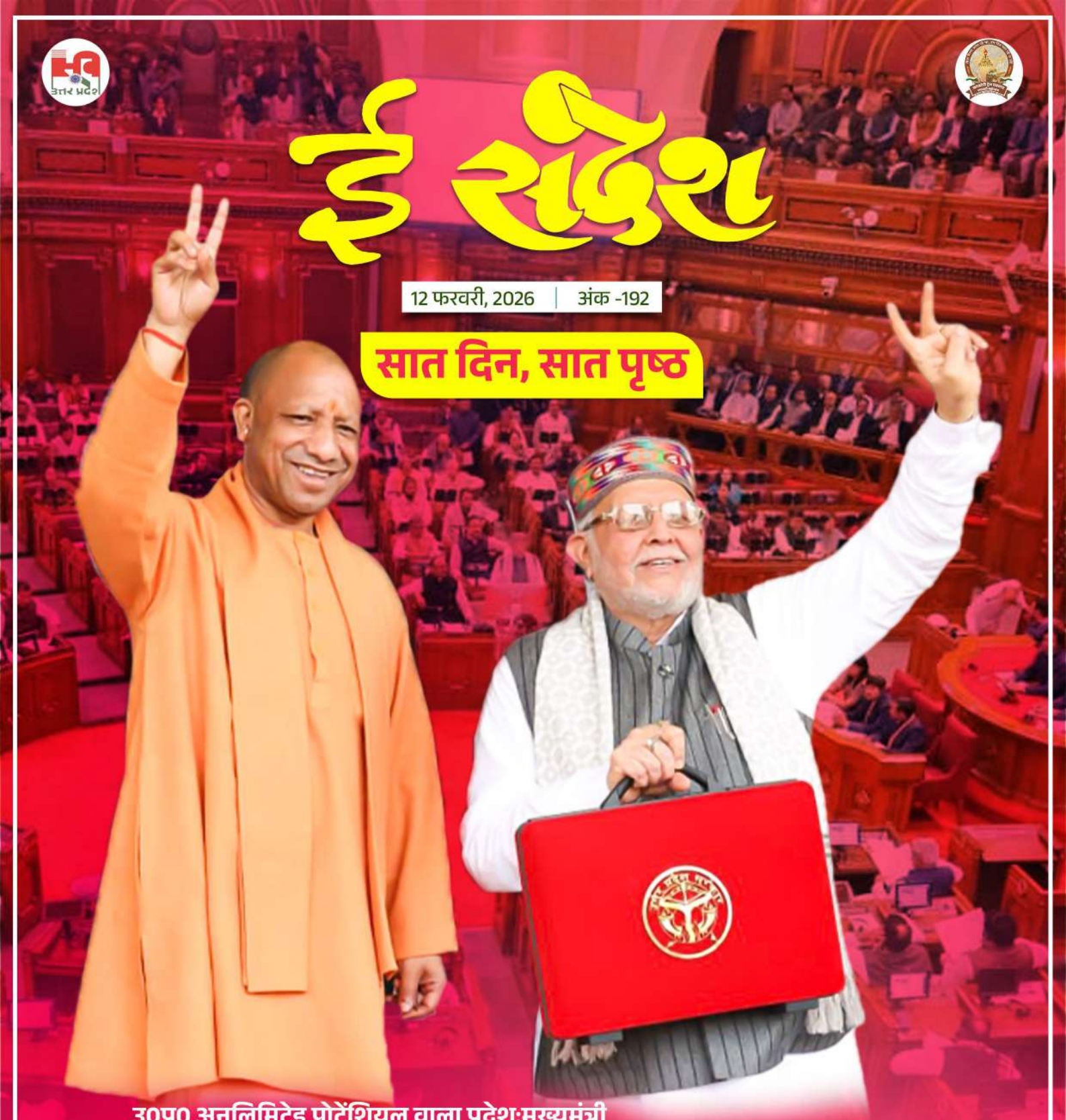

उ0प्र0 अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश:मुख्यमंत्री

बजट सत्र उ0प्र0 के विकास की स्पीड को और तीव्र करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा विधायी कार्यों को सम्पन्न करने तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी मंच बनेगा : मुख्यमंत्री

विकास की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जनपद बाराबंकी में एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा : मुख्यमंत्री

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के अन्तर्गत 250 शैय्या वाले लेवल-1 ट्रामा सेंटर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थापित किया जाएगा : मुख्यमंत्री

बजट प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत@2047 की संकल्पनाओं को समर्पित : मुख्यमंत्री

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

उ0प्र0 अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश:मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 05 फरवरी, 2026 को यहां उत्तर प्रदेश के प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण सम्भाविता पर आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2026-27 में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने नाबार्ड द्वारा तैयार राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन तथा ई-के0सी0सी0 पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने एफ0पी0ओ0, जिला सहकारी बैंक, महिला स्वयं सहायता समूह, पैक्स कम्प्यूटरीकरण तथा व्यावसायिक गतिविधि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित किया।

समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला प्रदेश है। हमारी कार्य क्षमता व दक्षता से अनलिमिटेड पोटेंशियल तब दिखाई देगी, जब विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश तथा आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त होगा। इस प्रकार के सेमिनार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस राज्य क्रेडिट सेमिनार में प्रगतिशील किसानों, एफ0पी0ओ0, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में कार्य करने वाले उद्यमियों और को-ऑपरेटिव सेक्टर में पैक्स के माध्यम से सहकारिता आन्दोलन को धरातल पर उतारने वाले महानुभावों की सक्सेस स्टोरी को सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य लोग भी इस दिशा में कार्य करते हुए इनकी सक्सेस स्टोरी का लाभ उठाकर अपने करियर को नई ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। नाबार्ड ने आज यहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले एफ0पी0ओ0, एस0एच0जी0, पैक्स, को-ऑपरेटिव बैंक्स को सम्मानित किया है। यह एक अच्छी पहल है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिव्यांगजन द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर कुशीनगर में स्थित है। दिव्यांगजन को अपनी सक्सेस स्टोरी रखने के लिए प्लेटफार्म मिलना चाहिए। इस मिल्क प्रोड्यूसर में 1005 सदस्य हैं। यह मिल्क प्रोड्यूसर बुन्देलखण्ड में स्थित बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर की तर्ज पर कार्य कर रहा है। दिव्यांगजन ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सेक्टर को मजबूत करते हुए लोगों की आंखें खोलने का अभिनन्दनीय कार्य किया है।

मथुरा में स्थित 750 महिला सदस्यों वाली मथुरा माँट मस्टर्ड उत्पादक कम्पनी मस्टर्ड ऑयल का प्रोसेसिंग कर अच्छा मुनाफा कमा रही है। हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। यदि अन्नदाता व प्रगतिशील किसानों, एम0एस0एम0ई0 सेक्टर में कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों, कारीगरों तथा सहकारिता के प्रति रुचि रखने वाले लोगों को थोड़ा भी हम प्रोत्साहित करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को स्थापित कर रहा है। आजादी के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय कार्य कर रहा है। एफ0पी0ओ0 तथा महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लखपति दीदी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में तैयार प्रोडक्ट को मार्केट से लिंक करने के लिए शी-मार्ट की स्थापना की व्यवस्था इस बार के यूनियन बजट में की गई है। अनेक प्रोत्साहनों तथा मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप सभी सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 'एक जनपद एक उत्पाद' योजना देश में ब्राण्ड बन चुकी है। प्रदेश में निर्यात 84,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 01 लाख 86,000 करोड़ रुपये हो चुका है। प्रधानमंत्री जी जब दुनिया के किसी देश में जाते हैं, तो वह वहां के राष्ट्राध्यक्षों को 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' योजना से जुड़े उत्पादों को उपहारस्वरूप प्रदान करते हैं। विगत 03 वर्षों से प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 'इण्टरनेशनल ट्रेड-शो' का आयोजन किया जा रहा है। गत वर्ष के आयोजन में प्रदेश के एफ0पी0ओ0 द्वारा किये गये बेहतरीन कार्य को सराहा गया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक सेक्टर में कुछ न कुछ नया कार्य हुआ तथा सम्भावनाओं को नई उड़ान मिली है। विगत दिनों सम्पन्न स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक में अवगत कराया गया कि आज से 09 वर्ष पूर्व प्रदेश में क्रेडिट-डेबिट (सी0डी0) रेशियो मात्र 43 प्रतिशत था, जो बढ़कर 61 प्रतिशत हो गया है।

इस रेशियो को प्रत्येक परिस्थिति में इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक 62 प्रतिशत तक पहुंचाना है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 65 प्रतिशत तय किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि को-ऑपरेटिव बैंकों का प्रयास होना चाहिए कि किसानों को 05 से 06 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएं। इस कार्य में सरकार उनका सहयोग करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के खाते में धनराशि भेजकर एम0एस0पी0 का लाभ प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के उपयोग की सम्भावनाओं के दृष्टिगत नए प्रयास को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से वर्तमान केन्द्रीय बजट में ए0आई0 कृषि प्लेटफार्म की घोषणा हुई है। इस दिशा में नए प्रयास को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश में को-ऑपरेटिव क्षेत्र का आधुनिकीकरण हो रहा है। 'सहकार से समृद्धि की ओर' के भाव के साथ डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से सहकारिता में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। प्रदेश सरकार देश में पहली बार विश्व बैंक के सहयोग से एग्रीटेक पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमें एग्रीकल्चर, एम0एस0एम0ई0, एग्रीटेक महिला, युवा उद्यमी पर फोकस करना होगा। बैंक की ब्याज दरों को कम तथा ट्रेनिंग पर कार्य करना होगा। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में क्लाइमेटिक तथा एग्रीकल्चर जोन के अनुसार कृषि विज्ञान केन्द्र तथा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं। यदि इन सब को केन्द्र बनाकर कार्य करेंगे तो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वर्ष 2027 में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने और वर्ष 2029-30 तक प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता मिलेगी।

बजट सत्र उ0प्र0 के विकास की स्पीड को और तीव्र करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा विधायी कार्यों को सम्पन्न करने तथा महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी मंच बनेगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 09 फरवरी 2026 कोविधान भवन परिसर में विधान मण्डल सत्र से पूर्व मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल में आज से बजट सत्र प्रारम्भ हो रहा है। वर्ष 2026-27 का सामान्य बजट आगामी 11 फरवरी को प्रस्तुत होगा और फिर इस पर चर्चा होगी। अन्त में अनुदान मांगों को पारित किया जाएगा। बजट सत्र आज 09 फरवरी से 20 फरवरी तक चलेगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल श्रीमती आनन्दीबेन पटेल जी का अभिभाषण और सामान्य बजट, यह बजट सत्र के दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं। संसदीय परंपरा के अनुरूप इसकी शुरुआत राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। राज्यपाल जी द्वारा समवेत सदन को अपना अभिभाषण संबोधन के माध्यम से दिया जाएगा। राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्ययोजना का एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी द्वारा सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता-जनार्दन को समर्पित किया जाता है। सभी सदस्य इस पर चर्चा करते हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के सदन के पटल पर रखे जाने के उपरान्त यह पहली बार होगा, जब उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक उपलब्धियों पर आधारित आर्थिक सर्वेक्षण भी सदन में प्रस्तुत किया जायेगा। हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से उबारकर भारत की इकोनॉमी के ब्रेक-थ्रू स्टेट के रूप में स्थापित किया है। उन सभी कारकों और उत्तर प्रदेश के आर्थिक उन्नयन की इस यात्रा को जानने का अधिकार सभी माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रदेश की जनता-जनार्दन को होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, आर्थिक उन्नयन, एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेशन की स्थिति में सुधार तथा प्रदेश के वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण आदि विषयों से सम्बन्धित आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत होगी। राज्य को पिछले 05 वर्ष से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया गया है। राज्यपाल जी के अभिभाषण और बजट पर चर्चा के दौरान सभी सदस्यों के लिए यह रिपोर्ट प्रदेश के डाटा का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधान मण्डल लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। यह संवाद से चलता है, कार्रवाई को बाधित करके नहीं। हमारी सरकार संवाद से समस्या के समाधान पर विश्वास करती है। सरकार प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा-परिचर्चा करने तथा सभी सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को स्वीकार करने को तैयार है। उन सुझावों पर चर्चा करके राज्य के हित में आवश्यक कदम उठाने के लिए तत्पर है। लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित न किया जाए और अनावश्यक शोर-गुल से बचा जाए।

मुख्यमंत्री जी ने सभी पक्षों के सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता-जनार्दन से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा करने तथा संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। विगत 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश विधान मंडल में कार्रवाई के नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट प्रस्तुत करने का है, ऐसे में यह सत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस पर पूरे प्रदेश और देश की निगाहें होंगी।

मुख्यमंत्री जी ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। यह अनेक प्रकार के विधायी कार्यों को सम्पन्न करने तथा समस्त सदस्यों के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने का भी एक मंच बनेगा।

राज्यपाल ने 09 फरवरी,2026 को उ0प्र0 राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के वर्ष-2026 के प्रथम सत्र के समवेत अधिवेशन को सम्बोधित किया।

विकास की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जनपद बाराबंकी में एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 फरवरी, 2026 को बाराबंकी भ्रमण के दौरान कहा कि विकास की परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए जनपद बाराबंकी में एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से जनपद के विकास को और अधिक गति मिलेगी। बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव मन्दिर में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए सरकार के स्तर से धनराशि आवंटित की जा चुकी है और शीघ्र ही कार्य प्रारम्भ होने वाला है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में भी भव्य कॉरिडोर बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने जनपद बाराबंकी में ब्रह्मलीन हिन्द केसरी पहलवान महन्त श्री हरिशंकर दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीराम जानकी मंदिर, बजरंग धाम व्यायामशाला में 'रामार्चा पूजा' में प्रतिभाग किया और आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हॉकी खिलाड़ी श्री के0डी0 सिंह बाबू की हवेली बिक रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि श्री के0डी0 सिंह बाबू की सेवाओं को देखते हुए उनकी हवेली को बिकने नहीं देगी। वहां भव्य स्मारक का निर्माण कराया जाएगा तथा उनकी स्मृतियों को संजोते हुए खेल की नई एकेडमी के निर्माण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि बाराबंकी का नौजवान श्री के0डी0 सिंह बाबू से प्रेरणा प्राप्त कर राष्ट्रीय खेल हॉकी से जुड़ सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डबल इंजन सरकार बाराबंकी के भविष्य को भी गौरवशाली बनाने के लिए कार्य कर रही है। यहां कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने तथा लोधेश्वर महादेव सहित अन्य पौराणिक स्थलों को जोड़ने के लिए मार्ग निर्माण हेतु धनराशि आवण्टित की जा चुकी है। इनमें कुछ कार्य प्रारम्भ हो चुके हैं। शेष कार्य प्रारम्भ होने वाले हैं। विकास कार्य अनवरत चलते रहेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। पहले वेतन देने के लिए भी पैसा नहीं था, आज सरकार के पास इतना पैसा है जिसका उपयोग हर एक तबके के विकास लिए किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के गरीब तथा संस्कृत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था बिना भेदभाव की जा रही है। पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था है तथा अच्छे संस्थान खोले जा रहे हैं। सरकार प्रत्येक तीर्थ स्थल के विकास के लिए कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार अपराध एवं अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेन्स की नीति के साथ कार्य कर रही है। विकास यात्रा में सरकार द्वारा किये गये कार्यों के कारण देश की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से उत्तर प्रदेश एक है।

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई के अन्तर्गत 250 शैय्या वाले लेवल-1 ट्रामा सेंटर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थापित किया जाएगा : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 10 फरवरी, 2026 को यहां लोक भवन में बतौर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) के अन्तर्गत 250 शैय्या वाले लेवल-1 ट्रॉमा सेण्टर की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि यह ट्रॉमा सेण्टर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के समीप स्थापित किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं सहित अन्य आपात परिस्थितियों में घायलों को त्वरित एवं उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे विश्वविद्यालय परिसर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके कारण दुर्घटना पीड़ितों के उपचार में बहुमूल्य समय नष्ट होता है। प्रस्तावित ट्रॉमा सेंटर का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय में 'सेण्टर फॉर रूरल हेल्थ' की स्थापना के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए, जिसमें टेली ओ0पी0डी0, वर्चुअल ओ0पी0डी0, डिजिटल डेटा एकीकरण तथा मोबाइल आउटरीच जैसी सेवाएं शामिल हों। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को नई दिशा देने से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई को पश्चिमी एवं मध्य उत्तर प्रदेश के लिए उच्चस्तरीय चिकित्सा, शिक्षण एवं शोध के प्रभावी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए। उपचार, शिक्षण और अनुसंधान के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्ता, संवेदनशीलता तथा समयबद्धता सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में नवाचारों को प्राथमिकता देने पर बल देते हुए कहा कि देश के अग्रणी चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थानों की श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) का अध्ययन कर उन्हें विश्वविद्यालय की व्यवस्था में समाहित किया जाए। विश्वविद्यालय से समाज की उच्च अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं, जिनकी पूर्ति के लिए हब-एण्ड-स्पोक मॉडल को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, ताकि सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में समग्र सुधार हो सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में इण्टीग्रेटिव मेडिसिन यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस इकाई के माध्यम से एलोपैथी एवं आयुष पद्धतियों के समन्वय से रोगी-केन्द्रित उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अन्तर्गत आयुष विभाग के सहयोग से इण्टीग्रेटिव ओ0पी0डी0, विशेष क्लीनिक, योग एवं वेलनेस इकाई स्थापित की जाएंगी।

स्वास्थ्य जागरूकता एवं जनसम्पर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये कि विश्वविद्यालय समाज के साथ प्रभावी संवाद स्थापित करे। इस क्रम में विश्वविद्यालय में कम्युनिटी ब्रॉडकास्ट सर्विस की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, रोग-निवारण, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं से सम्बन्धित प्रामाणिक जानकारी तथा शैक्षणिक सामग्री का प्रसारण किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 08 फरवरी, 2026 को राजभवन, लखनऊ में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से शिष्टाचार भेंट की।

बजट प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत@2047 की संकल्पनाओं को समर्पित : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 11 फरवरी, 2026 को सदन में 30प्र0 के वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तुतिकरण के उपरान्त प्रेसवार्ता को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश ने विगत 09 वर्षों के दौरान अपना परसेप्सन बदलने में सफलता प्राप्त की है। राज्य ने पॉलिसी पैरालिसिस से उबरकर अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया है। यह बजट इन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व करता है। विगत 09 वर्षों में प्रदेश का बजट तीन गुना से अधिक बढ़ा है। आज 09 लाख 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। 'सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान, हर हाथ को काम तथा नकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश' के लिए समर्पित यह बजट नव वर्ष के नवनिर्माण की नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट की हाइलाईट्स के अनुसार, 43,565 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए प्रस्तावित की गयी है। 02 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि कैपिटल एक्सपेंडीचर के लिए है। परिसम्पत्तियों के नवनिर्माण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट तथा अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार सृजन होता है। विगत 09 वर्षों में वर्तमान सरकार का 10वां बजट है। ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इन 09 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। प्रदेश में कर चोरी, लीकेज आदि को रोक कर कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश को बीमारू राज्य से अर्थव्यवस्था का ब्रेक-थ्रू तथा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता 30 प्रतिशत से अधिक थी, उसे हम 27 प्रतिशत लाने में सफल हुए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इसे 23 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। भारतीय रिर्जव बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की ऋणग्रस्तता उसकी जी0एस0डी0पी0 की 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में शामिल है, जिसने अपने वित्तीय प्रबंधन को एफ0आर0बी0एम0 की तय सीमा के अधीन रखा है। यह हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन प्रदर्शित करता है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश वेलफेयर व इन्फ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को धरातल पर उतारने के साथ प्रत्येक सेक्टर में ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नये प्रतिमान स्थापित कर रहा है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। राज्य देश की टॉप-थ्री अर्थव्यवस्था में एक है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2.24 प्रतिशत से कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2017 से पूर्व बेरोजगारी दर 17 से 19 प्रतिशत तक थी। वर्तमान बजट की सोच युवाओं के प्रति समर्पित है। प्रदेश में होने वाली ग्रोथ युवाओं के रोजगार से सम्बन्धित होनी चाहिए। इस पर ध्यान देते हुए एम0एस0एम0ई0, स्टार्टअप, ओ0डी0ओ0पी0 योजनाओं के अन्तर्गत स्थानीय उद्यमियों को ट्रेण्ड किया जा रहा है। निवेश की नई योजनाओं के साथ प्रदेश को इन्वेस्टमेण्ट डेस्टीनेशन तथा इम्प्लॉयमेण्ट जेनरेटर के रूप में बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में अक्सर देखने को मिलता था कि अलग-अलग विभाग अलग-अलग समय में अलग-अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। वर्तमान सरकार ने तय किया कि प्रदेश में 'स्टेट डाटा अथॉरिटी' का गठन किया जाएगा। यह अथॉरिटी रियल टाइम डाटा और रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगी। आज के बजट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित अनेक घोषणाएं हुई हैं। आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस तथा अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेण्टर क्लस्टर की स्थापना का प्राविधान किया गया है। मेडटेक व डीपटेक के लिए ए0आई0 मिशन की घोषणा से स्किल्ड युवा को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस बजट में आई0टी0 एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए विशेष प्राविधान किये गये हैं। 'उत्तर प्रदेश ए0आई0 मिशन' की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश में ए0आई0 सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस, और ए0आई0 डाटा लैब्स तथा साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेण्टर की स्थापना हेतु बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। सिटी इकोनॉमिक जोन, एस0सी0आर0, काशी-मीरजापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज-चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर-झांसी इकोनॉमिक जोन क्लस्टर डेवलपमेण्ट की नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के प्राविधान इस बजट में किये गये हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2017 में 'ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' में प्रदेश की रैंकिंग 13-14 पर थी। वर्तमान सरकार ने पहले 03 वर्षों में इसे दूसरे नम्बर पर लाने में सफलता प्राप्त की। प्रदेश ने चीफ अचीवर्स स्टेट के रूप में स्वयं को स्थापित किया। अब जन-विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेशकों के लिए 'सिंगल विण्डो' के माध्यम से लाइसेंसिंग, पंजीकरण आदि की कार्यवाही को अधिक सहज व सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

प्रदेश में डिजिटल इण्टरप्रेन्योरशिप योजना को आगे बढ़ाने की दिशा में बजट में प्राविधान किये गये हैं। इन कार्यों में हमें सफलता तब प्राप्त हुई है, जब प्रदेश में रूल ऑफ लॉ का वातावरण निर्मित किया गया। यही रियल ग्रोथ की गारण्टी है। स्मार्ट पुलिसिंग व त्वरित न्याय व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति व निवेशक को सुरक्षा तथा भरोसेमन्द वातावरण प्रदान करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करती है। इससे प्रदेश में रोजगार सृजित हुआ है। पहले कोई सोचता भी नहीं था कि प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होंगे। प्रदेश का एम0एस0एम0ई0 सेक्टर फिर से विकसित होकर 03 करोड़ से अधिक युवाओं के लिए रोजगार की सम्भावनाएं विकसित करेगा। आज यह सब उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्नदाता किसान भारत जैसे कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था और उसके विकास की धुरी हैं। हमारा किसान केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि विकास का भागीदार भी है। अब किसानों को अन्नदाता से उद्यमी बनाने की दिशा में नये प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि वह प्रदेश के विकास में सक्रिय साझेदार बनें। कृषि को इनकम बेस्ड व वैल्यू एडिशन मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए इस बजट में प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सिंचाई की क्षमता में अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। प्रदेश में 40 लाख ट्यूबवेल में से विद्युत से संचालित 16 लाख ट्यूबवेल के लिए निःशुल्क बिजली की व्यवस्था की गयी। डीजल से संचालित शेष 23 लाख ट्यूबवेल को फेजवाइज सोलर पावर से जोड़ने के लिए एक बड़ी योजना की घोषणा इस बजट में हुई है। इस योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला एवं सीमान्त किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान और अन्य किसानों के लिए 80 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गयी है। योजनान्तर्गत सोलर पैनल क्लस्टर व इण्डिविजुअल रूप से आगे बढ़ाते हुए इसमें पी0एम0 कुसुम योजना को भी सम्मिलित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष-2026 के उपलक्ष्य में बजट में एफ0पी0ओ0 को अतिरिक्त सुविधा से फैसिलिटेट करने के लिए रिवॉल्विंग फण्ड की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में गन्ना के साथ तिलहनी व दलहनी अन्तःफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में प्राविधान किये गये हैं। प्रदेश के किसानों के उत्पादों को निर्यात में सहायता प्रदान करने के लिए 'एग्री एक्सपोर्ट हब्स' के रूप में नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने की कार्रवाई आगे बढ़ायी गयी है। प्रदेश में कृषि व बागवानी उत्पादों की गुणवत्ता व उत्पादन में वृद्धि हेतु भी बजट में प्राविधान किये गये हैं।

वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर यूपी एग्रीज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। यू0पी0 एग्रीज के विस्तार तथा इसे ए0आई0 टूल्स के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गयी है। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना के लिए इस बजट में 02 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न भण्डारण की क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वेयरहाउस व बड़े-बड़े गोदाम बनें, इसके लिए विशेष सब्सिडी की व्यवस्था पॉलिसी के तहत राज्य में पहले से संचालित है। उस पॉलिसी के दायरे में जो भी निवेशक, निवेश करना चाहेगा, उसे सरकार प्रोत्साहित करेगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पशुओं को बीमा सुरक्षा देने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना' के अन्तर्गत 85 प्रतिशत तक प्रीमियम राज्य सरकार देगी। लैण्डलॉक्ड स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति देश में बहुत बेहतर है। प्रदेश में मछुआरों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 'स्टेट ऑफ द आर्ट होलसेल फिश मण्डी' और 'फिश प्रोसेसिंग सेण्टर' के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार वर्ल्ड फिशरीज प्रोजेक्ट सेण्टर की स्थापना के कार्य को आगे बढ़ा रही है, जो सेण्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में कार्य करेगा। प्रदेश की 04 चीनी मिलों की क्षमता संवर्धन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बजट में आगरा-लखनऊ-हरदोई-फर्रुखाबाद की गंगा एक्सप्रेस-वे से कनेक्टिविटी के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है। गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार प्रयागराज से मीरजापुर, वाराणसी, चन्दौली, सोनभद्र के शक्तिनगर तक तथा मेरठ से हरिद्वार तक किया जाएगा। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे को गाजीपुर से चन्दौली, सोनभद्र के शक्तिनगर तक ले जाने का कार्य किया जाएगा। यू0पी0 बायोफ्यूल प्लास्टिक केंद्र को विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। एफ0डी0आई0 फॉर्च्यून-500 के अन्तर्गत आने आने वाली कम्पनियों के लिए विशेष प्राविधान की घोषणा बजट में की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एम0एस0एम0ई0 सेक्टर को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुज़ीन योजना' के अन्तर्गत स्थानीय खाद्य पदार्थों की ब्राण्डिंग के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है। पुराने कम्बल/ऊन कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए इस बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद में हब एण्ड स्पोक मॉडल पर स्किल डेवलपमेण्ट के बड़े केन्द्र विकसित करने के कार्य को सरकार आगे बढ़ा रही है। इसके तहत सभी जनपदों में सरदार वल्लभभाई पटेल इन्प्लॉयमेण्ट जोन 50 एकड़ से लेकर 100 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित किये जाएंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए 'स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना' के अंतर्गत टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के लिए धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में कई मॉडल दिए हैं, जिनमें ऑपरेशन कायाकल्प, अटल आवासीय विद्यालय प्रमुख हैं। अटल आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में दो-दो सी0एम0 कम्पोजिट विद्यालय की स्थापना हेतु बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है। आवश्यकतानुसार विभिन्न विकास खण्डों में कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर कैशलेस उपचार की व्यवस्था बजट में की गयी है। इस कैसलेस उपचार व्यवस्था से सभी प्रकार के शिक्षकों को हमने जोड़ा है। बजट में बालिकाओं के लिए निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था की गई है। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इस बजट में की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग माध्यमिक स्तर से ही हम करना प्रारम्भ करें, इसके लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गई है। टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में प्रदेश सरकार ने शिक्षा, कौशल, तकनीक के सशक्त त्रिकोण को ध्यान में रखते हुए बजट में धनराशि का प्राविधान किया है। प्रदेश सरकार साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एण्ड मैथ्स (स्टेम) को बढ़ावा देने के लिए स्टेम ए0आई0 मिशन से राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थानों और टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन को जोड़ने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। इसके अन्तर्गत ए0आई0 इनबिल्ड लैब, स्किल डेवलपमेण्ट के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, ए0आई0 से जुड़ी सामग्री स्थानीय भाषा, अर्थात हिन्दी में उपलब्ध हो सके, इसके लिए कार्य हो रहा है। इस दिशा में नॉलेज पार्टनर के रूप में डीपटेक के लिए प्रदेश में आई0आई0टी0 कानपुर, आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 और अन्य संस्थाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए धनराशि की व्यवस्था बजट में की गई है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत 09 वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान से जुड़े कार्यक्रमों को ई-क्यूब अर्थात् इम्प्लॉयमेण्ट, इण्टरप्राइज तथा एक्सीलेंस के रूप में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में महिला श्रम बल 13 प्रतिशतसे बढ़कर 36 प्रतिशत हुआ है। इस महिला श्रम बल के प्रतिशत को और आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने 'महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना' के लिए धनराशि की व्यवस्था की है, जो शी-मार्ट की तर्ज पर कार्य करेगी। इसके माध्यम से गांवों व शहरी क्षेत्रों में लोकल स्तर पर प्रोडक्ट बनाने वालीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा 'महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड' की योजना भी घोषित की गई है, जिसके अन्तर्गत महिलाओं की आय बढ़ाने, लखपति दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाने, ब्याजमुक्त पूंजी उपलब्ध कराने हेतु धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है। कामकाजी महिलाओं के लिए प्रत्येक जनपद स्तर पर श्रमजीवी महिला छात्रावास के निर्माण हेतु धनराशि का प्राविधान इस बजट में किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए 'वन कमिश्नरी-वन स्पोर्ट्स कॉलेज' अर्थात 18 कमिश्नरी हेड क्वार्टर्स पर एक-एक स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित किया जाएगा, ताकि वर्ष 2030 में अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स तथा वर्ष 2036 में ओलम्पिक की भारत प्रस्तावित दावेदारी के दृष्टिगत प्रदेश के युवा बड़ी संख्या में इन आयोजनों के भागीदार बन सकें। इन स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही उन्हें एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स के लिए सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। इसके लिए बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है।

खेलो इण्डिया कार्यक्रम के अन्तर्गत ओपन जिम, खेल के मैदान, मिनी स्टेडियम तथा स्टेडियम का निर्माण कराते हुए उन्हें विकसित करने की दिशा में भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द जी के नाम पर जनपद मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया जा रहा है, जो आगामी अप्रैल-मई तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस यूनिवर्सिटी में सत्र प्रारम्भ हो चुका है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश ने लम्बी छलांग लगायी है। वर्ष 2017 से पूर्व प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण तथा अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रदेश का पर्सेप्शन देश और दुनिया में खराब था। यहां पर न तो पर्यटन सुविधाएं थीं और न ही उसके विकास के लिए सरकार की रुचि थी। सुरक्षा के अभाव के कारण कोई पर्यटक यहां आने का प्रयास नहीं करता था। वर्ष 2024-25 में 122 करोड़ पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों, ईको-टूरिज्म, हेरिटेज-टूरिज्म एवं एडवेन्चर से जुड़े अन्य पर्यटन केन्द्रों पर यात्रा की। पर्यटन स्वयं में रोजगार सृजन का बड़ा माध्यम है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए बजट में धनराशि का प्राविधान किया गया है। एक नई व्यवस्था करते हुए 01 लाख अतिरिक्त रूम जोड़ने की दिशा में पर्यटन पॉलिसी के अन्तर्गत पी0पी0पी0 मोड पर कार्य किया जाएगा। 50 हजार नये होम-स्टे के लिए भी कार्य किया जाएगा। महिला गाइड प्रशिक्षण के लिए लगने वाले 10 हजार रुपये के लाइसेन्स शुल्क को माफ करने की भी बजट में व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विगत 09 वर्षों में नई प्रगति की है। प्रदेश में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 17 से कम सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। आज प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज, 02 एम्स तथा अनेक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल कार्यरत हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अर्न्तगत 05 करोड़ 46 लाख से अधिक गोल्डेन कार्ड बनाने राज्य वाला है। हम मेडिकल कॉलेजों को टर्शियरी केयर के रूप में विकसित कर रहे हैं। प्रत्येक जनपद में डायलिसिस, रेडियोलॉजी, एम0आर0आई0, सी0टी0 स्कैन, कलर डॉप्लर, डिजिटल एक्स-रे की व्यवस्था करने के साथ ही उसे नेक्स्ट स्तर पर ले जाने हेतु इस बजट में प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एस0जी0पी0जी0आई0 देश का पहला सेन्टर होगा, जहां टर्शियरी के बाद क्वाटरनरी हेल्थ केयर सेन्टर की स्थापना की जाएगी। यह एक बड़ा कार्य है, जिसके लिए पहले चरण में 250 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। एस0सी0पी0जी0आई0 का यह सेन्टर प्रदेश में ऑर्गन ट्रान्सप्लाण्ट के अभियान को आगे बढ़ाएगा। उन जनपदों में जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज के साथ सम्बद्ध किया गया है, वहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। 'राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन' के अन्तर्गत 'राज्य वन हेल्थ मिशन' तथा मेडिकल कॉलेजों में छात्रावास के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक प्राविधान करने के साथ-साथ यदि कोई घटना-दुर्घटना या कोई आपदा आती है, तो उन परिस्थितियों में ट्रॉमा सेन्टर को सशक्त बनाने तथा नए ट्रॉमा सेन्टर विकसित करने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में मेडिकल तथा हेल्थ सेक्टर में मेड-टेक की स्थापना होनी चाहिए। इसमें ए0आई0, रोबोटिक आदि की सहायता से देश-प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों सहित जनपदों में सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। राज्य सरकार ने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ तथा आई0आई0टी0 कानपुर में 02 सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाने हेतु धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उच्च शिक्षा में बेटियों विशेषकर मेरिटोरियस छात्राओं को स्कूटी देने के लिए बजट में धनराशि की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश की बेटियों को सशक्त बनाने हेतु स्मार्टफोन/टैबलेट की अतिरिक्त व्यवस्था उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा, प्रदेश में दिव्यांगजन कल्याण के अन्तर्गत स्कूल में अथवा ट्रेनिंग ले रही किसी दिव्यांग छात्रा के लिए ई-ट्राई साइकिल अर्थात मोटराइज्ड ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने के लिए भी व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में डी0डी0आर0सी0 की स्थापना हो, जहां दिव्यांगजन हेतु नजदीकी सेन्टर में कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के लिए स्क्रीनिंग और उपकरण वितरण किया जा सके, इसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है।

03 से 07 वर्ष के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु डे-केयर सेन्टर की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या, मथुरा, झांसी, मुजफ्फरनगर, देवरिया, जौनपुर जनपदों में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी बजट में व्यवस्था की गयी है। 09 जनपदों-गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ, बरेली, झांसी, मेरठ और आगरा में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए प्राविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत/2047 की संकल्पनाओं को समर्पित है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की है। प्रदेश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। विगत 09 वर्षों में उत्तर प्रदेश 'बॉटल नेक' की जड़ता तथा बीमारू स्टेट को समाप्त करते हुए भारत की इकोनॉमी का 'ब्रेक-थ्रू-स्टेट' के रूप में विकसित होने की दिशा आगे बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के वित्त मंत्री द्वारा विधान सभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट उत्तर प्रदेश में जन आकांक्षाओं को पूरा करने, जनकल्याण, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन, निवेश का विस्तार, महिलाओं का सम्मान और उनके सशक्तिकरण को आगे बढ़ाएगा। यह उत्तर प्रदेश को वर्ष 2029-30 में 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के रूप में प्रस्तुत करते हुए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री जी ने दूरदर्शी जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले, युवा, महिला, अन्नदाता किसान और गरीब को ध्यान में रखकर बनाए गये इस बजट के लिए वित्त मंत्री व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री ब्रजेश पाठक तथा मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि सभी की मेहनत और सकारात्मक योगदान से प्रदेश का परसेप्शन बदला है। सभी सहयोगियों ने नई भूमिका को प्रस्तुत किया है। सिस्टम वही है, लेकिन जब लीडरशिप बदलती है, तो कैसे चेंज आता है। वह चेंज आज यहां पर इस बजट के माध्यम से देखने को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश 09 लाख 12 हजार करोड़ रुपये के बजट को प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है।